Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में उच्च शिक्षा संस्थानों की सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ शशिरंजन अकेला
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश

सारांश
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को समाज–उन्मुख, उत्तरदायी और समावेशी बनाने की दिशा में एक निर्णायक दस्तावेज़ है। यह नीति उच्च शिक्षा संस्थानों को केवल ज्ञान–प्रदान के केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक सशक्तिकरण और सतत विकास के सक्रिय भागीदार के रूप में स्थापित करती है। प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में उच्च शिक्षा संस्थानों की सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता की भूमिका का विश्लेषण करना है।

प्रस्तुत अध्ययन में सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा, सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा संचालित ग्रामीण आउटरीच एवं सामुदायिक योजनाएँ, 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' योजना की प्रासंगिकता, डिजिटल मंचों की भूमिका, सतत विकास लक्ष्यों (विशेषतः एसडीजी–4) से संबंध, सामुदायिक समस्याओं पर केंद्रित अनुसंधान परियोजनाएँ, प्रमुख चुनौतियाँ तथा भविष्य की रणनीतियों का समग्र विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन द्वितीयक समंकों, नीति–दस्तावेज़ों और शोध साहित्य पर आधारित है। निष्कर्षतः यह पाया गया कि सामुदायिक सहभागिता उच्च शिक्षा को अधिक प्रासंगिक, व्यावहारिक और सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनाती है, तथा यह नीति 2020 के उद्देश्यों की पूर्ति का एक प्रभावी माध्यम है।

शब्दकुंजी :– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सामुदायिक सहभागिता, सामाजिक उत्तरदायित्व, उच्च शिक्षा, सतत विकास।

1. भूमिका :–

उच्च शिक्षा किसी भी राष्ट्र के बौद्धिक विकास, सामाजिक चेतना और आर्थिक प्रगति का आधार होती है। परंपरागत रूप से उच्च शिक्षा संस्थान ज्ञान–उत्पादन और मानव संसाधन निर्माण तक सीमित माने जाते रहे हैं, किंतु बदलते सामाजिक–आर्थिक परिवेश में उनकी भूमिका का विस्तार अनिवार्य हो गया है। बढ़ती सामाजिक विषमता, ग्रामीण–शहरी अंतर, बेरोज़गारी, डिजिटल डिवाइड तथा पर्यावरणीय संकटों ने शिक्षा को समाज से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

उच्च शिक्षा किसी भी राष्ट्र की बौद्धिक चेतना, सामाजिक संरचना और दीर्घकालिक विकास का मूल आधार होती है। समकालीन युग में जब समाज तकनीकी परिवर्तन, वैश्वीकरण, रोजगार की बदलती प्रकृति, सांस्कृतिक पुनरावर्तन तथा सतत विकास की जटिल चुनौतियों से गुजर रहा है, तब उच्च शिक्षा की भूमिका केवल ज्ञान–प्रदान तक सीमित नहीं रह सकती। इसी व्यापक संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक, दूरदर्शी और परिवर्तनकारी दस्तावेज़ के रूप में सामने आती है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, बहुविषयक, गुणवत्तापूर्ण और समाज–उन्मुख बनाना है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

चित्र क्रमांक – 1
उच्च शिक्षा के संदर्भ में एनईपी 2020

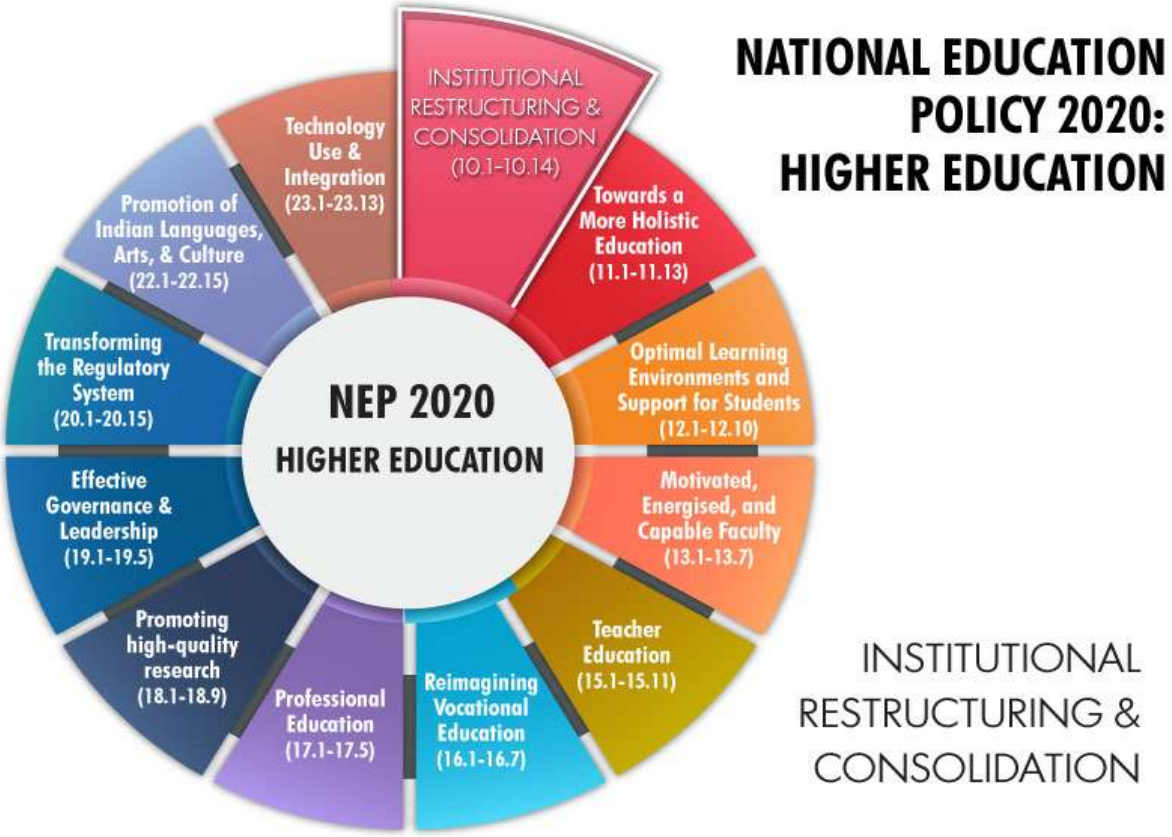

चित्र में समग्र शिक्षा की ओर अग्रसर होने, विद्यार्थियों के लिए अनुकूल अधिगम परिवेश तथा समुचित सहयोग की व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को केवल परीक्षा और उपाधि तक सीमित नहीं रखती, बल्कि विद्यार्थियों के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को समान रूप से महत्व देती है। ऐसा दृष्टिकोण उच्च शिक्षा को समाज से जोड़ने और सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ करने की ठोस आधारशिला प्रदान करता है।

शिक्षकों की भूमिका को नीति में केंद्रीय स्थान दिया गया है। चित्र में प्रेरित, ऊर्जावान और सक्षम शिक्षक वर्ग तथा शिक्षक शिक्षा पर बल यह दर्शाता है कि किसी भी शैक्षिक परिवर्तन की सफलता शिक्षकों की गुणवत्ता और प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। जब शिक्षक बहुविषयक दृष्टि, सामाजिक संवेदनशीलता और नवीन शिक्षण पद्धतियों से युक्त होंगे, तब वे विद्यार्थियों को सामुदायिक अध्ययन, सामाजिक सेवा और समाजोपयोगी अनुसंधान के लिए प्रेरित कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक एवं पेशेवर शिक्षा की पुनर्कल्पना को चित्र में प्रमुख स्थान दिया गया है। यह पहल शिक्षा को आजीविका, कौशल विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास करती है। इससे उच्च शिक्षा संस्थानों और स्थानीय समुदायों के बीच सशक्त संबंध स्थापित होते हैं तथा शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनती है।

चित्र में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान के संवर्धन, प्रभावी प्रशासन एवं नेतृत्व, नियामक व्यवस्था के रूपांतरण, भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के प्रोत्साहन तथा प्रौद्योगिकी के समुचित उपयोग जैसे

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

घटक यह स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाते हुए भी उसे भारतीय सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का संतुलित प्रयास करती है। यह संतुलन उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समस्याओं पर कार्य करते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम बनाता है।
इस प्रकार, प्रस्तुत चित्र के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा को एक समाज–संलग्न, उत्तरदायी और बहुविषयक प्रणाली के रूप में पुनर्गठित करने का सशक्त प्रयास है। इसी व्यापक दृष्टि के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों में सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक उत्तरदायित्व को एक अनिवार्य आयाम के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रस्तुत शोधपत्र इसी संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में उच्च शिक्षा संस्थानों की सामुदायिक भूमिका का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो शिक्षा को समाज से सार्थक रूप से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

2. अध्ययन के उद्देश्य :–

- सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता की अवधारणा को स्पष्ट करना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका का विश्लेषण करना।

3. शोध पद्धति :–

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसमें द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है, जिनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यूजीसी एवं एआईसीटीई की मार्गदर्शिकाएँ, सरकारी रिपोर्टें, जर्नल लेख, पुस्तकें तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के दस्तावेज़ सम्मिलित हैं।

4. सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता की अवधारणा :–

सामाजिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा समाज के प्रति अपनी नैतिक, बौद्धिक और विकासात्मक ज़िम्मेदारियों के निर्वहन से है। वहीं सामुदायिक सहभागिता एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है, जिसमें संस्थान और समुदाय परस्पर सहयोग से ज्ञान, अनुभव और संसाधनों का आदान–प्रदान करते हैं। तालिका 1 में उच्च शिक्षा संस्थानों की सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता के प्रमुख आयामों को स्पष्ट किया गया है। शैक्षणिक आयाम के अंतर्गत सेवा–शिक्षण और समुदाय आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों से जोड़ा जाता है, जिससे सैद्धांतिक ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग संभव होता है।

तालिका 1

सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता के प्रमुख आयाम

आयाम	विवरण
शैक्षणिक	सेवा–शिक्षण, समुदाय आधारित पाठ्यक्रम
सामाजिक	स्वास्थ्य, स्वच्छता, साक्षरता अभियान
आर्थिक	कौशल विकास, स्वरोज़गार प्रशिक्षण
सांस्कृतिक	स्थानीय संस्कृति एवं भारतीय ज्ञान का संरक्षण
पर्यावरणीय	स्वच्छता, जल संरक्षण, हरित पहल

सामाजिक आयाम में स्वास्थ्य, स्वच्छता और साक्षरता से संबंधित अभियानों द्वारा समुदाय की जीवन–गुणवत्ता में सुधार का प्रयास किया जाता है, साथ ही छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता और नागरिक दायित्व की भावना विकसित होती है। आर्थिक आयाम कौशल विकास एवं स्वरोज़गार प्रशिक्षण पर केंद्रित है, जिसके माध्यम से स्थानीय युवाओं की आजीविका के अवसर बढ़ते हैं और क्षेत्रीय आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिलता है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

सांस्कृतिक आयाम के अंतर्गत स्थानीय संस्कृति, लोकज्ञान और परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन पर ध्यान दिया जाता है, जिससे सांस्कृतिक पहचान बनी रहती है और पीढ़ियों के बीच ज्ञान का हस्तांतरण होता है। वहीं पर्यावरणीय आयाम, स्वच्छता, जल संरक्षण और हरित पहलों के माध्यम से पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देता है, जो सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार, ये सभी आयाम मिलकर उच्च शिक्षा संस्थानों को समाज के प्रति अधिक उत्तरदायी और सहभागितापूर्ण बनाते हैं।

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उच्च शिक्षा संस्थान :–

एनईपी 2020 उच्च शिक्षा को बहु–विषयक, लचीला और समाज–उन्मुख बनाने पर बल देती है। नीति के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदायों के साथ जुड़कर अनुसंधान, नवाचार और सेवा गतिविधियाँ संचालित करनी चाहिए, ताकि शिक्षा का प्रत्यक्ष सामाजिक प्रभाव सुनिश्चित हो सके।

6. यूजीसी एवं एआईसीटीई की सामुदायिक एवं ग्रामीण आउटरीच योजनाएँ :–

यूजीसी एवं एआईसीटीई द्वारा संचालित योजनाएँ उच्च शिक्षा को समुदाय से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

तालिका 2

प्रमुख सामुदायिक एवं ग्रामीण आउटरीच योजनाएँ

संस्था	योजना	उद्देश्य
यूजीसी	यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी	समाजोपयोगी गतिविधियाँ
यूजीसी	एनएसएस तथा विस्तार गतिविधियाँ	छात्र सहभागिता
एआईसीटीई	उन्नत भारत अभियान	ग्रामीण समस्याओं का समाधान
एआईसीटीई	स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन	नवाचार आधारित समाधान

उपरोक्त तालिका में उच्च शिक्षा को समाज से जोड़ने हेतु यूजीसी एवं एआईसीटीई द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं को दर्शाया गया है। यूजीसी की 'यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी' पहल के अंतर्गत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप समाजोपयोगी गतिविधियाँ संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उच्च शिक्षा संस्थान सामाजिक विकास के सक्रिय केंद्र के रूप में कार्य कर सकें। इसी क्रम में एनएसएस तथा विस्तार गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वैच्छिक सेवा, सामुदायिक जागरूकता अभियानों और सामाजिक कार्यों से जोड़ा जाता है, जिससे उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व, नेतृत्व क्षमता और नागरिक चेतना का विकास होता है। दूसरी ओर, एआईसीटीई की 'उन्नत भारत अभियान' योजना तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़कर वहाँ की वास्तविक समस्याओं–जैसे कृषि, जल, ऊर्जा, स्वच्छता और आजीविका के समाधान हेतु प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप को बढ़ावा देती है। वहीं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के माध्यम से विद्यार्थियों और युवा नवाचारकों को शासन, उद्योग और समाज से जुड़ी जटिल समस्याओं के लिए रचनात्मक एवं नवाचार आधारित समाधान विकसित करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार, ये सभी योजनाएँ उच्च शिक्षा को अकादमिक सीमाओं से आगे ले जाकर समाज–उन्मुख, व्यावहारिक और विकासोन्मुख बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

7. एक भारत–श्रेष्ठ भारत योजना की प्रासंगिकता :–

यह योजना भारतीय समाज की बहुलता में निहित एकता को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल है। यह योजना केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा, उसकी सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक है। 31 अक्टूबर 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

मोदी द्वारा प्रारंभ की गई यह योजना भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक, भाषायी और सामाजिक सेतु निर्माण का प्रयास करती है। इसका मूल उद्देश्य "विविधता में एकता" के भारतीय दर्शन को व्यावहारिक स्तर पर सुदृढ़ करना है।

इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में जोड़ा जाता है, ताकि वे एक–दूसरे की भाषा, साहित्य, लोककला, परंपराओं, खानपान, पर्व–त्योहार और जीवन–शैली को समझ सकें तथा आत्मसात कर सकें। यह प्रक्रिया किसी औपचारिक अध्ययन तक सीमित न होकर जीवंत सांस्कृतिक अनुभवों के माध्यम से होती है, जिससे आपसी सम्मान, सहिष्णुता और भावनात्मक जुड़ाव विकसित होता है। इस दृष्टि से यह योजना भारत को एक "सांस्कृतिक ताने–बाने" की तरह प्रस्तुत करती है, जहाँ प्रत्येक राज्य एक विशिष्ट रंग के रूप में संपूर्ण राष्ट्र की सुंदरता को और अधिक समृद्ध बनाता है।

उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका इस योजना के क्रियान्वयन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और तकनीकी संस्थान छात्रों को विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क का अवसर प्रदान करते हैं। छात्र विनिमय कार्यक्रम, सांस्कृतिक शिविर, भाषा कार्यशालाएँ, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएँ और सामुदायिक अध्ययन जैसी गतिविधियों के माध्यम से युवा पीढ़ी न केवल अन्य क्षेत्रों की संस्कृति को समझती है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता के मूल्यों को भी आत्मसात करती है। इस प्रकार, उच्च शिक्षा संस्थान इस योजना को वैचारिक से व्यावहारिक स्तर तक ले जाने में सेतु का कार्य करते हैं।

सामुदायिक सहभागिता के संदर्भ में 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' योजना विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि यह छात्रों और शिक्षकों को स्थानीय समुदायों के साथ प्रत्यक्ष संवाद और सहभागिता का अवसर देती है। जब विद्यार्थी किसी अन्य राज्य या क्षेत्र के समुदाय के साथ कार्य करते हैं, तो वे सामाजिक संरचनाओं, स्थानीय समस्याओं और सांस्कृतिक संदर्भों को गहराई से समझ पाते हैं। इससे शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित न रहकर सामाजिक अनुभव और मानवीय संवेदनाओं से समृद्ध होती है।

इसके अतिरिक्त, यह योजना भाषायी समझ को भी बढ़ावा देती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का आधार है। विभिन्न भाषाओं के अध्ययन और प्रयोग से छात्रों में भाषायी सहिष्णुता, संवाद कौशल और सांस्कृतिक सम्मान का विकास होता है। यह प्रक्रिया दीर्घकाल में राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करती है।

समग्र रूप से देखा जाए तो 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' योजना उच्च शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता और राष्ट्रीय एकता के बीच एक सशक्त कड़ी स्थापित करती है। यह योजना न केवल भारत की सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करती है, बल्कि उसे साझा अनुभव और आपसी सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय शक्ति में परिवर्तित करती है। इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समाज–उन्मुख और मूल्य–आधारित शिक्षा के दृष्टिकोण के अनुरूप, 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' योजना उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करती है, जिससे वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय और अर्थपूर्ण भूमिका निभा सकें।

8. डिजिटल मंचों की भूमिका :–

डिजिटल मंचों ने सामुदायिक सहभागिता को व्यापक स्वरूप प्रदान किया है। ऑनलाइन शिक्षा, वेबिनार, डिजिटल सर्वे और ई–आउटरीच के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थान दूरस्थ एवं वंचित समुदायों तक पहुँच बना रहे हैं।

चित्र क्रमांक–2

डिजिटल मंच और सामुदायिक सहभागिता का संबंध

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

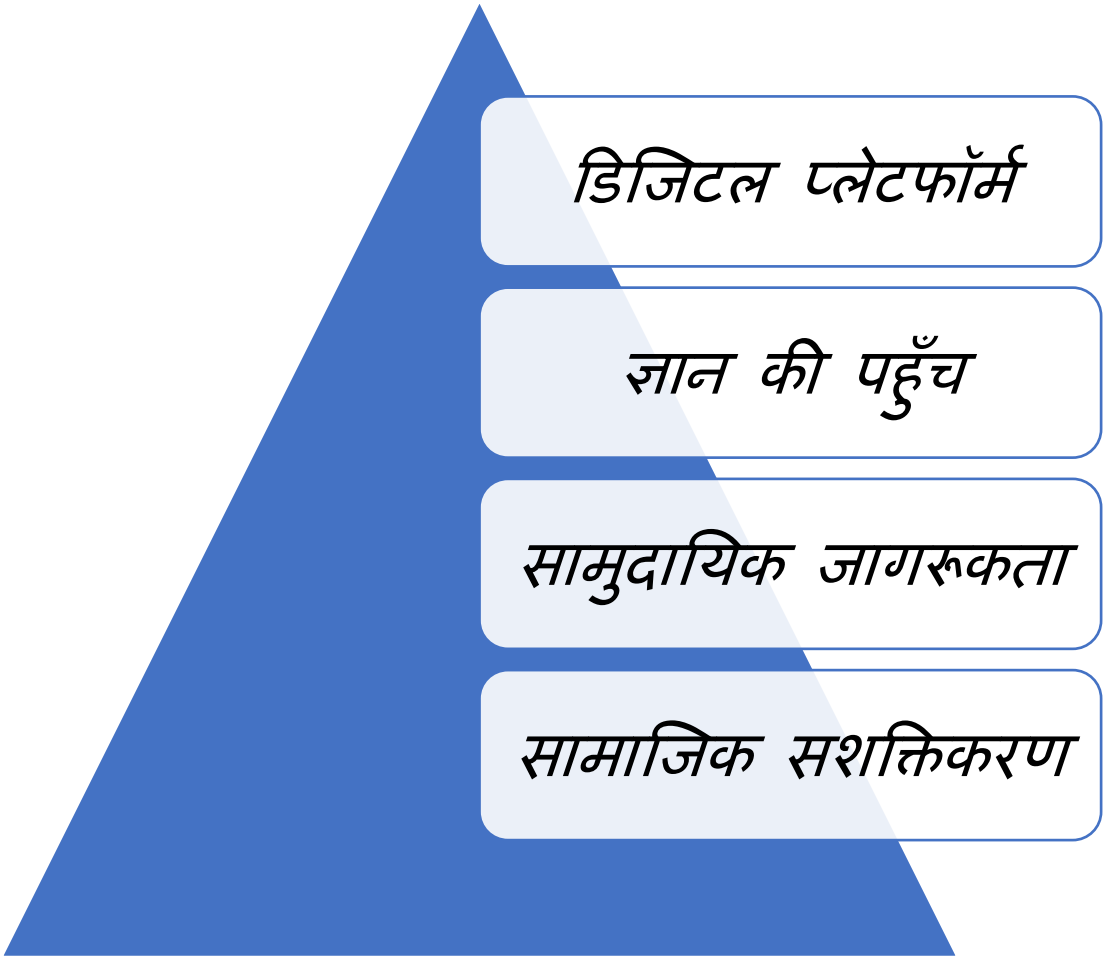

9. सतत विकास और एसडीजी –4 की भूमिका :–

एसडीजी –4 गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा पर केंद्रित है। सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थान शिक्षा को आजीवन सीखने और सतत विकास से जोड़ते हैं।

तालिका: 3

उच्च शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और सतत विकास लक्ष्य–4 के बीच प्रमुख भूमिकाएँ एवं संबंध

क्र.	प्रमुख क्षेत्र	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका	सतत विकास लक्ष्य–4 से संबंध
1	शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच	उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात को वर्ष 2035 तक 5 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य	सभी के लिए समावेशी एवं समान शिक्षा की उपलब्धता
2	समानता एवं सामाजिक समावेशन	वंचित वर्गों, महिलाओं एवं पिछड़े समुदायों पर विशेष बल	शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता को कम करना

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

3	आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल	रटंत पद्धति के स्थान पर समझ, चिंतन और समग्र विकास पर ज़ोर	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नींव सुदृढ़ करना
4	बहुविषयक एवं समग्र शिक्षा	एकांगी शिक्षा के स्थान पर बहुविषयक विश्वविद्यालयों की स्थापना	आजीवन सीखने के अवसरों का विस्तार
5	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास	कक्षा छह से व्यावसायिक शिक्षा का चरणबद्ध समावेशन	रोजगारोन्मुख शिक्षा द्वारा सतत आजीविका
6	शिक्षक गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण	सतत व्यावसायिक विकास और शिक्षक शिक्षा में सुधार	शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि
7	अनुसंधान एवं नवाचार	उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को प्रोत्साहन	ज्ञान–आधारित और सतत समाज का निर्माण
8	मूल्य आधारित एवं नैतिक शिक्षा	संवैधानिक मूल्यों, पर्यावरणीय चेतना और नागरिक उत्तरदायित्व पर बल	जिम्मेदार एवं जागरूक नागरिकों का निर्माण
9	संस्थागत पुनर्संरचना	बड़े, स्वायत्त एवं बहुविषयक संस्थानों का विकास	शिक्षा व्यवस्था की दीर्घकालिक स्थिरता
10	आजीवन अधिगम	बहु–प्रवेश और बहु–निकास प्रणाली	जीवनभर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का स्वरूप सतत विकास लक्ष्य–4 (एसडीजी –4) के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसका उद्देश्य समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा आजीवन सीखने के अवसर प्रदान करना है। तालिका 3 से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूल उद्देश्य उच्च शिक्षा में सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना, समानता को बढ़ावा देना और शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना है, जो सतत विकास लक्ष्य–4 के केंद्रीय भाव से पूर्णतः मेल खाता है। नामांकन अनुपात में वृद्धि, वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल पर बल तथा बहुविषयक शिक्षा की परिकल्पना शिक्षा को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाती है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से शिक्षा को आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ा गया है, जिससे सतत आजीवन विकास को समर्थन मिलता है। साथ ही, शिक्षक गुणवत्ता, अनुसंधान, मूल्य आधारित शिक्षा और संस्थागत पुनर्संरचना जैसे प्रावधान शिक्षा प्रणाली को दीर्घकालिक रूप से सक्षम बनाते हैं। इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न केवल सतत विकास लक्ष्य–4 के उद्देश्यों को साकार करने का माध्यम है, बल्कि उच्च शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकास की सशक्त आधारशिला के रूप में स्थापित करती है। मूल्य–आधारित शिक्षा, पर्यावरणीय जागरूकता और जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देकर एनईपी 2020 एक ऐसे सतत भविष्य की नींव रखती है, जिसमें शिक्षित नागरिक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास में सक्रिय योगदान देने में सक्षम हों।

10. सामुदायिक समस्याओं पर केंद्रित अनुसंधान परियोजनाएँ :–

एनईपी 2020 स्थानीय समस्याओं पर आधारित अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है, जैसे–ग्रामीण आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा में ड्रॉप–आउट, जल एवं पर्यावरण।

11. चुनौतियाँ :–

- संसाधनों एवं वित्त का अभाव
- अकादमिक दबाव
- समुदाय एवं संस्थान के बीच समन्वय की कमी

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

- मूल्यांकन तंत्र का अभाव

12. भविष्य की रणनीतियाँ :–

- सेवा–शिक्षण को पाठ्यक्रम का अनिवार्य भाग बनाना
- सामुदायिक कार्य को क्रेडिट प्रणाली से जोड़ना
- स्थानीय सरकार एवं एनजीओ के साथ साझेदारी
- डिजिटल एवं हाइब्रिड सहभागिता मॉडल

13. उपसंहार :–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक दूरदर्शी एवं परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थानों को केवल ज्ञान–प्रदान तक सीमित न रखकर समाज के साथ सक्रिय सहभागिता करने वाली उत्तरदायी संस्थाओं के रूप में देखा गया है। सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक उत्तरदायित्व को शिक्षा की मूलधारा में सम्मिलित करके यह नीति शिक्षा और समाज के बीच लंबे समय से विद्यमान दूरी को पाटने का प्रयास करती है।

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका अब केवल शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य, स्वच्छता, साक्षरता, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक संवर्धन जैसे क्षेत्रों में भी सार्थक योगदान देना होगा। यूजीसी, एआईसीटीई एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएँ इस दिशा में संस्थागत समर्थन प्रदान करती हैं, जबकि 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' जैसी पहलें राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक समझ को सुदृढ़ करती हैं।

डिजिटल मंचों के प्रभावी उपयोग तथा सतत विकास लक्ष्यों, विशेषतः एसडीजी –4, के साथ संरेखण के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और आजीवन सीखने की प्रक्रिया के रूप में स्थापित करती है। साथ ही, सामुदायिक समस्याओं पर केंद्रित अनुसंधान एवं नवाचार शिक्षा को व्यावहारिक और समाजोपयोगी बनाते हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन, पर्याप्त संसाधन उपलब्धता और संस्थागत प्रतिबद्धता के साथ किया जाए, तो उच्च शिक्षा संस्थान सामाजिक परिवर्तन, सतत विकास और राष्ट्र निर्माण के सशक्त माध्यम बन सकते हैं। इस प्रकार, सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक उत्तरदायित्व न केवल उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, बल्कि एक समावेशी, सशक्त और संवेदनशील भारतीय समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संदर्भ

1. Government of India. (2020). *National Education Policy 2020*. Ministry of Education.
2. UGC. (2021). *Guidelines for Community Engagement and Extension Activities*.
3. AICTE. (2022). *Unnat Bharat Abhiyan Guidelines*.
4. UNESCO. (2017). *Education for Sustainable Development Goals*.
5. United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.